Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

# केसीसी योजना (किसान क्रेडिट कार्ड योजना) में सहकारी बैंकों की भूमिका : देवास जिले के विशेष संदर्भ में

**डॉ. जी एल खगोडे*  श्रीमती स्वाति राठौड़****

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस माधव आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस माधव आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश –** भारत एक कृषि प्रधान देश है। सभ्यता के प्रारंभ से ही कृषि कार्य भारतीय जनसंख्या की जीविका उपार्जन के लिए आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत रहा है। भारतीय कृषि प्रणाली में कृषकों के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण एवं जटिल कार्य है। मुख्यत: छोटे एवं सीमांत कृषकों को कई बार कृषि संबंधी अपनी वित्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए गैर-संस्थागत ऋणप्रदान कर्ताओं तथा साहूकारों पर आश्रित होना एक मजबूरी है। साहूकारों द्वारा भी उच्च ब्याज दरों से किसने की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका शोषण किया जाता रहा है। कई किसान साहकारों के ऋण एवं ब्याज के कर्ज तले दयनीय जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं, यहां तक की कई कृषकों द्वारा ऋणग्रस्तता के चलते आत्महत्या भी कर ली जाती है, इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में केसीसी योजना प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य कृषकों को कम ब्याज दरों पर आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराना था।

प्रस्तुत शोध आलेख में मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में केसीसी योजना द्वारा कृषकों के ऋण वितरण में 'सहकारी बैंकों' की भूमिका का अध्ययन किया गया है। इस शोध आलेख में विश्लेषण किया गया है की केसीसी योजना के परिणाम स्वरुप किसानों की आय में सुधार हुआ है, उनकी ऋण शोधन क्षमता, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि उत्पादन क्षमता में योजना के परिणाम स्वरुप सुधार हुआ है। शोध के निष्कर्ष के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है की केसीसी योजना के सफल क्रियान्वयन में सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों की ऋण उपलब्धता में सुगमता हुई है, जिससे उनके जीवन स्तर तथा उनकी आय में सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं।

**शब्द कुंजी –** केसीसी योजना, ब्याज, ऋण, ऋणदाता, सहकारी बैंक, फसल चक्र, आर्थिक स्थिति।

**प्रस्तावना –** भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र के 70 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है तथा उनकी आजीविका मुख्य साधन कृषि ही है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि का अतुलनीय योगदान है। इसीलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए तथा कृषकों को समय पर वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ही सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण प्रयास केसीसी योजना है। जिसके अंतर्गत किसानों को खेती से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य के लिए तथा उनके वित्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के फल स्वरुप किसानो की साहूकारों पर निर्भरता कम हुई है। विभिन्न वाणिज्य एवं सहकारी बैंक इस योजना के क्रियान्वयन में तथा आर्थिक विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत सम्पूर्ण भारत में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री 'श्री यशवंत सिन्हा' दवारा वर्ष 1998-99 के बजट भाषण में इस योजना का परिचय देते हुए प्रारंभ की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना नाबार्ड की एक मॉडल स्कीम के आधार पर तैयार की गई थी जो विभिन्न वाणिज्यक एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई गई। केसीसी योजना के अंतर्गत किसानों को बिना किसी गिरवी के 1.6 लाख तक तथा गिरवी रखकर रूपये 3 तक का ऋण 2 प्रतिशत ब्याज की छूट के साथ प्रदान किया जाता है। किसान लिए गए ऋण भुगतान अपनी सुविधाअनुसार फसल का कटाई एवं फसल के विक्रय के बाद भी कर सकते हैं, इस योजना में यह सुविधा होने के कारण किसानों में केसीसी योजना ज्यादा लोकप्रिय हुई है।

**साहित्य समीक्षा**

1. हिरवे चौधरी और वानखेड़ा (2016) में 'मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर ब्लॉक में कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केसीसी प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन' किया है। प्राथमिक डाटा के संकलन के लिए बहुस्तरीय नामूनाकरण विधि का उपयोग किया गया है। जिसमें एक ब्लॉक के 10 गांव का चयन किया गया है। जिसमें प्रत्येक गांव के 15 उत्तरदाताओं को चुना गया है। डेटा का विश्लेषण प्रतिशत, आवृति, माध्य, मानक विचलन, टी-परीक्षण का उपयोग किया गया है। तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए क्षेत्र में तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है।
2. कनेल (2016) में 'मध्य प्रदेश के धार जिले में कृषि अर्थव्यवस्था पर केसीसी योजना के प्रदर्शन और प्रभाव का अध्ययन' किया है। प्राथमिक डाटा संकलन में 80 लाभार्थी किसानों तथा 80 गैर लाभार्थी किसानों से प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से डाटा एकत्र किया गया है। चयनित बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट से दवितीय डाटा एकत्र किया गया है। प्राथमिक डेटा

विश्लेषण के लिए औसत, प्रतिशत, सारणी तथा द्वितीय डाटा के विश्लेषण के लिए सीएजीआर तकनीक का उपयोग किया गया है। अध्ययन से पता चला कि 2003-04 से 2014-2015 की अवधि के लिए केसीसी की विकास दर 1.12%प्रतिशत रही हैं।

3. एंडोत्रा और गुप्ता (2015) ने कहा कि 'केसीसी प्रणाली का कृषि उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव' पड़ा है। इस अध्ययन में शामिल की गई फसलों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है जो यह दर्शाता है कि कृषि उत्पादन बड़ा है। उत्पादन स्तर पर वृद्धि का मुख्य कारण केसीसी योजना के माध्यम से किसानों को प्रीमियम इनपुट के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराना है।

4. मीना (2013) ने 'राजस्थान के करौली क्षेत्र में किसानों की आय पर केसीसी के सूक्ष्म स्तर पर प्रबंधन और उसके प्रभाव का मूल्यांकन' किया। इस अध्ययन का उद्देश्य केसीसी के विकास का मूल्यांकन करना, ऋण प्राप्ति के पैटर्न का विश्लेषण करना और किसानों की आय पर केसीसी के प्रभाव का अध्ययन करना है। 2001-02 से 2010-11 के वार्षिक डेटा से डाटा एकत्रितकरण किया गया है। 60 केसीसी धारक तथा 60 गैर केसीसी धारक किसानों का चयन करके प्राथमिक सामंक को प्राप्त किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र योजना का मुख्य आधार है, जिसमें वाणिज्य बैंक तथा सहकारी बैंकों की मुख्य भूमिका रही है।

5. शर्मा, चौधरी और स्वर्णकार (2013) ने 'मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों पर इसके प्रभाव का अध्ययन' किया है। प्राथमिक डाटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 3750 लाभार्थियों में से यादृशिक रूप से चुने गए 120 लाभार्थियों से एकत्र किया गया है। डेटा विश्लेषण के लिए प्रतिशत परिवर्तन तथा आवृत्ति वितरण विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है की केसीसी कार्डधारक किसान संभवत: अपने जमा राशि का उपयोग उच्च गुणवता वाले फसल इनपुट प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। अध्ययन में शामिल अधिकांश किसान नियमित रूप से ऋण का भुगतान कर रहे हैं तथा लाभार्थियों का रवैया भी संतोषजनक पाया गया है।

**केसीसी योजना का उद्देश्य एवं महत्व-** 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना' एक वित्तीय योजना है जो किसानों को कृषि संबंधित कार्यों के लिए उचित समय पर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। इस योजना के फलस्वरूप कितने ही साहूकारों तथा गैर संस्थागत ऋणों पर निर्भरता कम हुई है तथा उनकी ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि हुई।

**उद्देश्य:**

1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को सरल एवं त्वरित वित्त सुविधा उपलब्ध कराना है।
2. गैर संस्थागत ऋण तथा साहूकारों के उच्च ब्याज दरों से कृषक वर्ग के शोषण को रोकना है।
3. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को कषि संबंधी विभिन्न कार्य, मछली पालन, पशुपालन, डेयरी संबंधित कार्यों के लिए उचित समय पर ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
4. सहकारिता एवं वाणिज्य बैंकों के माध्यम से सुगमता पूर्वक कृषकों तक वितीय सहायता उपलब्ध कराना।

**महत्व:**

1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए किसान खाद बीज उर्वरक, कीटनाशक तथा नकदी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2. इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्र्वेशन तथा समय पर भुगतान करने पर प्रोत्साहन मिलता है जो किसी अन्य योजना में नहीं मिलता है, इसलिए यह योजना कृषक वर्ग में ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है।
3. इस योजना के अंतर्गत रिवाल्विंग क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाती है, यानी किसान अपनी फसल उत्पादन के पश्चात ऋण का भुगतान कर सकता है।
4. शोध क्षेत्र (देवास जिला) में यह देखा गया है कि इस योजना के परिणाम स्वरुप किसानों की आय स्थिर हुई है तथा उनकी साहूकारों पर निर्भरता कम हुई है।
5. कृषि उपकरण की खरीद को केसीसी योजना द्वारा संभव बनाया जा सका है।
6. लाभार्थी किसानों को इस योजना के अंतर्गत रूपये 50,000 तक का दुर्घटना बीमा मिलना योजना को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है।

**देवास जिले में किसान क्रेडिट कार्ड का प्रभाव -** प्रस्तुत शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना देवास जिले के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिदधै हई है, क्योंकि इस योजना के फलस्वरूप कितने ही आय, उनका जीवन स्तर तथा उनकी ऋण शोधन क्षमता में उत्तरोतर वृद्धि हुई है। जिसे निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है-

**1. फसल उत्पादन में वृद्धि :** किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू होने के बाद किसान आधुनिक तकनीकी तथा आधुनिक कृषि यंत्रों से परिचित हुए हैं, जिससे उनकी फसल का उत्पादन बड़ा है और फसल उत्पादन बढ़ाने के परिणाम स्वरूप उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा ऋणग्रस्तथा के चंगुल से बाहर निकलने में सफल रहे हैं।

**2. ऋण शोधन क्षमता में वृद्धि :** इस योजना का सबसे अहम बिंदु यह है कि इसमें ऋण लेने के पश्चात किसान अपनी फसल की कटाई तथा उसके विक्रय करने के बाद अपना ऋण का भुगतान कर सकता है जिससे किसानों को ऋण के दबाव से निजात मिली है तथा वह आसानी से फसल विक्रय के पश्चात अपने ऋण का भुगतान करके शासकीय योजना का लाभ लेने में सफल हुए हैं।

**3. कृषकों की आय में सुधार :** इस योजना के सफल क्रियान्वयन में वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों के महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केसीसी योजना में आसान शर्तों पर त्वरित ऋण प्राप्त होने से किसानों की आय तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। शोध अध्ययन से यह जानकारी स्पष्ट हुई कि इस योजना के फलस्वरुप किसानों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आय में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे किसान अपने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ अपने बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रहा है।

**केसीसी योजना के सफल क्रियान्वयन में सहकारी बैंक की भूमिका-** देवास जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति में सहकारी बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। जिले में योजना की बैंकवार प्रगति के रूप में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक डीसीसीबी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि देवास जिले का अधिकांश भूभाग कृषि कार्य के रूप में प्रयुक्त होता है, तथा केसीसी योजना को गति प्रदान करने में सहकारी बैंक की अहम भूमिका रही है।

योजना को सफल बनाने में अन्य वाणिज्यिक बैंक जैसे बैंक आफ इंडिया का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है लेकिन डीसीसीबी की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है।

जिले में केसीसी ऋण वितरण में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अग्रणी है वर्ष 2024-25 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 176009 किसानों को केसीसी ऋण जारी किए गए हैं। इसी के साथी सहकारी बैंक द्वारा लाभान्वित कृषिकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। देवास सहकारी बैंक किसानों को केसीसी के माध्यम से फसल ऋण, कोर बैंकिंग, ATM और RuPay KCC जैसी सुविधाए भी प्रदान करता है। वर्ष 2024-25 में सहकारी बैंक ने 11 करोड रुपए का लाभ अर्जित किया जो इस बैंक की वितीय मजबूती को दर्शाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 शुरू की गई थी ताकि किसानों को बीज, कीटनाशक, उर्वरक तथा विभिन्न कृषि उपकरण खरीदी में मदद की जा सके। वर्ष 2004 में गैर कृषि गतिविधियों संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे संशोधित भी किया गया। इस के साथ ही वर्ष 2020 में संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जरूरत को पूरा करने के लिए सिंगल विंडो के माध्यम से ऋण प्रदान करने का प्रयास किया गया, जिसमें अल्पावधि ऋण आवश्यकता, फसल कटाई के बाद का खर्च, कृषि उपज विपणन ऋण तथा कृषि संपत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी आदि सुविधाएं भी शामिल की गई।

**तालिका - किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या**

| वर्ष | जारी किए गए कार्डस (लाख में) | स्वीकृत राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|
| 2019-20 | 109 | 36,350 |
| 2020-21 | 82 | 2,34,420 |
| 2021-22 | 75 | 3,19,751 |
| 2022-23 | 48 | 2,17,710 |
| 2023-24 | 31.40 | 6,11,431 |

नोट- वर्ष 2019-20 की राशि सिर्फ सहकारी बैंकों के आंकड़े हैं जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आंकड़े शामिल नहीं है क्योंकि उसे समय आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया गया था। वर्ष 2022-23 का आंकड़ा सितंबर 2022 तक का है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन किसानों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2023-24 के आंकड़े 29 मार्च 2024 तक के हैं जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम चरण को दर्शाते हैं।

स्त्रोत: लोकसभा आतरंकित प्रश्न संख्या 1051, 13 दिसंबर 2022

**किसानों का वर्गीकरण-** भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार स्तंभ भारत का किसान ही है जिसका पूरा ध्यान रखना भारत के नागरिको तथा सरकार का दायित्व भी है। चुकी विश्व भर में भारत की पहचान एक समृद्ध कृषि प्रधान देश के रूप में की जाती है, दैनिक जीवन की भी बहुत सी आवश्यकता तथा खाद्य सामग्री के लिए हम प्राथमिक रूप से कृषि पर ही निर्भर है।

**कृषकों के वर्गीकरण का आधार -** भारत में क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात के दृष्टिकोण से हम किसानों को समान रूप से नहीं देख सकते। समग्र विकास को देखते हुए भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषक वर्ग को भिन्न-भिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के क्रम में जोड़ा गया है। कृषकों कोलाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं को किसानों तक पहुंचने में भी भूमि का आधार ही महत्वपूर्ण रहता है। कृषि की नवीनतम कृषि जनगणना 2015-16 में भारत में किसानों का भूमि के आधार पर 5 आकार में वर्गीकरण किया गया है। यह वर्गीकरण परिचालन जोत के आधार पर आधारित है जो नीतिगत योजनाओं के लिए उपयोगी है।

| क्र. | किसानों का वर्ग | भूमिका हैक्टयर मे | एकड़ में |
|---|---|---|---|
| 1 | सीमांत | 1 हैक्टयर से कम | 2.47 एकड़ |
| 2 | छोटा | 1 से 2 हैक्टयर | 2.47 से 4.94 एकड़ |
| 3 | अर्ध मध्यम | 2 से 4 हेक्टयर | 4.94 से 9.88 एकड़ |
| 4 | मध्यम | 4 से 10 हैक्टयर | 9.88से 24.71 एकड़ |
| 5 | बड़ा | 10 हैक्टयर से अधिक | 24.71 एकड़ |

**निष्कर्ष -** प्रस्तुत शोध का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के सफल क्रियान्वयन में देश में विद्यमान वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यह योजना न केवल किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है बल्कि किसानों को गैर संस्थागत ऋण तथा साहूकारों के चंगुल से बचाने में भी सफल रहे हैं। इस योजना के लागू होने के पूर्व किसानों को गैर संस्थागत ऋण पर आश्रित रहना पड़ता था, जहां उच्च ब्याज दर से ब्याज देने के लिए किसान मजबूर रहते थे, किंतु इस योजना के लागू होने के पश्चात किसानों को ऋण उपलब्धता आसान हुई है। इस योजना में समय पर ऋण का भुगतान करने पर किसानों को छूट भी प्राप्त होती है इसलिए किसान लाभ प्राप्त करने के लिए ऋण चुकाने में भी जागरुक हुए हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इस योजना के फल स्वरुप ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के किसान कृषि की आधुनिक तकनीक से भी परिचित हुए हैं, परिणाम स्वरूप तकनीकी उन्नति को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिला है। योजना के सफल क्रियान्वयन का यह प्रभाव हुआ है कि किसान पारंपरिक खेती के स्थान पर तकनीकी आधारित खेती करने लगे हैं जिससे उनका जीवन स्तर तथा आय में सुधार हुआ है।

हालांकि इस योजना में कुछ चुनौतियां भी है जिनमें सुधार की जरूरत आज भी विद्यमान है। वर्तमान में भी कई किसान इस योजना से आज भी अनभिज्ञ हैं और इसका लाभ लेने से वंचित है। प्रथम दृष्टियां देखा गया है कि बैंकिंग जटिल प्रणाली से भी किसान योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचितरह रहे हैं, अगर इस योजना के नियम शर्ते क्रियान्वयन को और आसन तथा पारदर्शी बनाया जा सके तो और अधिक किसान इस योजना से लाभार्थी हो सकते हैं। किंतु अंतत: या कहा जा सकता है कि सहकारी बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों के सहयोग से किसान क्रेडिट कार्ड योजना अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल रही है।

**सुझाव एवं सिफारिश -** चुकी किसान 'क्रेडिट कार्ड योजना' अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रही है, तथा योजना के लाभार्थी किसानों का जीवन स्तर शिक्षा स्वास्थ्य तथा उनके उत्पादन क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। फिर भी इस योजना को और प्रभावशाली तथा सफल बनाने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

1. सर्वप्रथम तो हम सुझाव देना चाहेंगे कि इस योजना में महिला उद्यमी/ महिला किसान तथा छोटे किसान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि उनकी छोटी-छोटी वित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

2. केसीसी योजना में ऋण सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि किसानों को अधिक मात्रा में वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो सके
3. कृषि संबंधी उपकरणों के लिए भी अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि तकनीकी कृषि और आधुनिक कृषि से भी परिचित हो सके।
4. विभिन्न डिजिटल माध्यम, फ्लेक्स तथा विज्ञापनों के माध्यम से केसीसी योजना का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि वंचित किस भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
5. जागरूकता रैलियो का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि देश का प्रत्येक किसान वर्ग इस योजना का लाभ समय सीमा पर प्राप्त करके अपने जीवन स्तर तथा अपने बच्चों का भविष्य निर्माण अच्छे से कर सके।
6. किसानों को डिजिटल बैंकिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए तथा डाटा डिजिटाइजेशन एवं ऑनलाइन ऋण आवेदन प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि किसानों को ऋण प्राप्त करने के लिए बार-बार बैंकों के चक्कर काटने की समस्या समाप्त की जा सके।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. कृषि मंत्रालय भारत सरकार (2020) 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक विस्तृत विश्लेषण' नई दिल्ली कृषि एवं सहकारिता विकास।
2. मध्य प्रदेश सहकारी बैंक (2022) 'जिला सहकारी बैंकों की भूमिका उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में' भोपाल मध्य प्रदेश सहकारी बैंक रिपोर्ट।
3. यादव एस (2021) 'मध्यप्रदेश में सहकारी बैंकों का विकास एवं भूमिका' भोपाल मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण।
4. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ( 2019) कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड एक आर्थिक अध्ययन आरबीआई मुंबई प्रकाशन।
5. कृषि योजना समिति (2020) 'आरत में कृषि ऋण सुधार में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका' नई दिल्ली नीति आयोग की रिपोर्ट।

**********